सिर्फ 2 .68 लाख कमा रहा भारतीय

केजरीवाल का भाजपा पर हमला, बोले- बांग्लादेश से भी पीछे भारत

नई दिल्ली, 21 अगस्त. दुनिया के कई अमीर देश भारी सरकारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं, लेकिन उनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से कई गुना अधिक है. दूसरी ओर भारत का कर्ज-जीडीपी अनुपात करीब 55-56 प्रतिशत के आसपास है और प्रति व्यक्ति आय करीब 2,800 डॉलर है.

ऐसे में दुनिया के अलग-अलग देशों की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए केवल कर्ज या केवल प्रति व्यक्ति आय को देखना पर्याप्त नहीं है. दोनों आंकड़ों को साथ रखकर तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होती है. जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. उपलब्ध आंकड़ों में उसका सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 200 प्रतिशत से अधिक है, जबकि प्रति व्यक्ति आय करीब 34 हजार डॉलर यानी 32.5 लाख रुपये सालाना है. आईएमएफ के 2026 के अनुमान में जापान का सरकारी कर्ज अनुपात करीब 204.4 प्रतिशत है. वहीं सिंगापुर का कर्ज अनुपात भी 170 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन उसकी प्रति व्यक्ति आय करीब 90 हजार डॉलर के आसपास है. इसके बावजूद सिंगापुर की वित्तीय स्थिति को केवल सकल कर्ज के आंकड़े से आंकना सही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बड़ी सरकारी वित्तीय संपत्तियां भी हैं. अमेरिका का कर्ज भी जीडीपी के मुकाबले 120 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 80 हजार डॉलर से ज्यादा है. फ्रांस और इटली जैसे विकसित देशों में भी कर्ज का अनुपात 100 प्रतिशत से ऊपर है. ग्रीस, बहरीन और मालदीव जैसे देशों में भी कर्ज का बोझ काफी ऊंचा है.

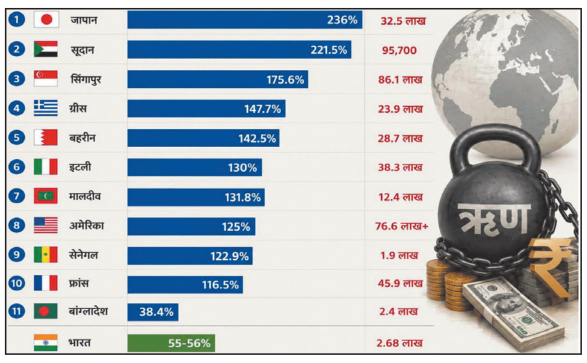

> भारत की प्रति व्यक्ति आय को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत बांग्लादेश से भी पीछे रह गया है. आईएमएफ के अप्रैल 2026 के अनुमान के मुताबिक, भारत की नाममात्र प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,812 डॉलर है, जबकि बांग्लादेश की 2,911 डॉलर. यानी बांग्लादेश भारत से करीब 99 डॉलर आगे है.

नराकास दिल्ली-2 की 17वीं छमाही बैठक

नयी दिल्ली. 21 अगस्त को अंशुली आर्या, आई.ए.एस., सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा डॉ. विकास कुमार, अध्यक्ष, नराकास दिल्ली (उपक्रम-2) एवं प्रबंध निदेशक, डीएमआरसी ने एनबीसीसी के हिंदी गृह पत्रिका के 20वें संस्करण के प्रकाशन एवं राजभाषा के उत्कृष्ट प्रचार-प्रसार के लिए टी. डी. मैराल, महाप्रबंधक (मा.सं.प्र./ आईआर/ राजभाषा) एवं अन्य अधिकारियों को प्रशंसा स्वरूप ट्रॉफी/शील्ड प्रदान की. इसके अतिरिक्त, इसी बैठक के दौरान व्यक्तिगत कर्मचारी श्रेणी में जय राम, एजीएम (वित्त), सुश्री वंदना ओझा, प्रबंधक (राजभाषा), रमेश कुमार वैश्य, प्रबंधक तथा अरविंद कुमारवास्तव, कार्यपालक को भी विभिन्न राजभाषा प्रतियोगिताओं में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया.

थाली से गायब हुई हरी सब्जी

200 रुपए किलो पहुंचा धनिया

55 रुपए के पार पहुंची प्याज

60 रुपए किलो पहुंचे भिंडी, लौकी

भोपाल, 21 अगस्त. बारिश ने जहां मौसम को सुहाना किया है, वहीं रसोई का बजट बिगाड़ दिया है. देश के कई हिस्सों में हरी सब्जियों की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिल रहा है.

दो महीने पहले तक करीब 10 रुपए किलो में बिकने वाली भिंडी अब कई बाजारों में 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है. लौकी, नेनुआ, तोरई, बैंगन, करेला, परवल और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के भाव भी बढ़कर करीब 60 रुपए किलो के आसपास पहुंच गए हैं. सबसे ज्यादा हैरानी धनिया के भाव ने बढ़ाई है. खुदरा बाजार में धनिया करीब 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि मुंबई में इसका भाव करीब 60 रुपए किलो बताया जा रहा है. गांव और छोटे शहरों के बाजारों में भी धनिया और अदरक महंगे बिक रहे हैं. पुराना अदरक कई जगह 300 से 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है. कारोबारियों के मुताबिक, लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में लगी सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ है. कई स्थानों पर खेतों में पानी भरने से फसल खराब हुई और मंडियों में सब्जियों की आवक घट गई.

> हालांकि वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही में महंगाई घटकर करीब 5 फीसदी पर आने का अनुमान है. सब्जियों और चीनी जैसी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम परिवारों के मासिक बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को इसका ज्यादा असर झेलना पड़ सकता है. आने वाले दिनों में यदि बारिश का दौर जारी रहा और सब्जियों की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो कीमतों में और तेजी की आशंका बनी रह सकती है.

छोटे कारोबार को सरकारी सहारा, 10 लाख तक मदद

मशीन से ब्रांडिंग तक मदद, छोटे उद्यमियों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग

बेकरी, अचार, पापड़, मसाले जैसे कारोबारों को बढ़ाने का अवसर

नई दिल्ली, 21 अगस्त. घर से अचार, पापड़, मसाले, मिठाई, बेकरी उत्पाद या दूसरी खाद्य सामग्री बनाकर कारोबार करने वाले छोटे उद्यमियों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना कारोबार को आगे बढ़ाने का रास्ता खोल रही है.

योजना के तहत पात्र सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बैंक से जुड़े ऋण पर परियोजना लागत की 35 प्रतिशत तक पूंजी सब्सिडी मिल सकती है. इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति इकाई है. खास बात यह है कि योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्यमियों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, ब्रांडिंग और विपणन में भी सहयोग दिया जाता है. इसका उद्देश्य छोटे और असंगठित खाद्य कारोबारों को व्यवस्थित करना और उन्हें बड़े बाजार से जोड़ना है.किसे मिल सकता है लाभ? योजना के तहत व्यक्तिगत कारोबारी के साथ स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और सहकारी संस्थाएं भी पात्रता के अनुसार लाभ ले सकती हैं. जो लोग पहले से खाद्य प्रसंस्करण का छोटा कारोबार चला रहे हैं, वे उसे आधुनिक बनाने के लिए सहायता ले सकते हैं. वहीं पात्रता पूरी करने वाले नए उद्यमी भी कारोबार शुरू करने के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं.

> **संजीत की बदली जिंदगी :** बिहार के शेखपुरा जिले के भदौली गांव के संजीत कुमार ने इस योजना का लाभ लेकर अपने कारोबार को नई दिशा दी. वह पहले गांव के चौक पर कपड़ों की दुकान चलाते थे. सीमित आमदनी के कारण परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था. योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने उद्योग विभाग से संपर्क किया और आवेदन किया. सहायता मिलने के बाद उन्होंने बेकरी की मशीनें खरीदीं और कारोबार शुरू किया.

टाटा की सैटेलाइट इंटरनेट में होगी एंट्री

2028 तक शुरू होगी डी2डी सेवा

2026 के अंत तक परीक्षण शुरू करने की तैयारी

नई दिल्ली, 21 अगस्त भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में अब टाटा समूह की कंपनी नेल्को भी उतरने की तैयारी कर रही है. कंपनी वर्ष 2028 तक डायरेक्ट-टू-डिवाइस (डी2डी) सैटेलाइट सेवा शुरू करने की योजना बना रही है. इसके लिए इस साल के अंत तक परीक्षण शुरू किए जाने की संभावना है.

डी2डी तकनीक के तहत मोबाइल फोन या अन्य संगत उपकरण सीधे सैटेलाइट से संपर्क कर सकेंगे, जिससे उन दूरदराज के इलाकों में भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, जहां मोबाइल टावर लगाना मुश्किल या महंगा है.

टाटा समूह की इस पहल से भारत में सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढने् की उम्मीद है. हालांकि नेल्को की रणनीति जियो और स्टारलिंक से कुछ अलग होगी.

कंपनी सीधे उपभोक्ताओं को सेवा देने के बजाय मोबाइल और दूरसंचार कंपनियों के साथ साझेदारी कर व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) और व्यवसाय-से-सरकार (बी2जी) क्षेत्र में काम करने पर ध्यान देगी.

> **संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी को नया विकल्प**
> नेल्को की योजना मोबाइल कनेक्टिविटी के अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट कृषि और अन्य क्षेत्रों में भी डी2डी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की है. कंपनी भारत के साथ बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे बाजारों में भी अपनी सेवाओं के विस्तार की तैयारी कर रही है. यदि योजना के अनुसार सेवा शुरू होती है, तो दूरसंचार नेटवर्क की पहुंच से बाहर रहने वाले क्षेत्रों में संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी को नया विकल्प मिल सकता है.

दिन भर के उतार-चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुआ सेंसेक्स

नयी दिल्ली, 21 अगस्तविदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को उतार-चढ़ाव देखा गया और बीएसई का सेंसेक्स अंत में सपाट बंद हुआ.

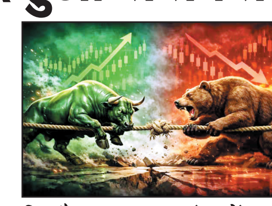

सेंसेक्स आज 163 अंक चढ़कर 77,701.07 अंक पर खुला. बीच कारोबार में यह ऊपर 77,725 अंक और नीचे 77,446 अंक तक गया. अंत में 3.11 अंक की बढ़त में 77,540.83 अंक पर बंद हुआ.नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 20.15 अंक यानी 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,252 अंक पर रहा. पिछले कारोबारी दिवस पर दोनों प्रमुख सूचकांक मजबूत बंद हुए थे.वृहत बाजार में भी सभी सूचकांक ऊपर बंद हुए. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक में 0.11 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक में 0.69 प्रतिशत की तेजी रही.सेक्टर आधारित सूचकांकों में निफ्टी बैंकिंग और निफ्टी वित्त हरे निशान में रहे. एफएमसीजी, ऑटो, आईटी, मीडिया और रसायन समूहों में गिरावट देखी गयी.

सेंसेक्स की कंपनियों में पावरग्रिड का शेयर ढाई फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ. बीईएल और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर एक प्रतिशत से अधिक चढ़े.

चेन्नई जल व्यवस्था के लिए 23 करोड़ डॉलर का ऋण

नयी दिल्ली, 21 अगस्त केंद्र सरकार ने चेन्नई में जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार 23 करोड़ डॉलर के ऋण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.

वित्त मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ऋण के लिए बातचीत वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव (एडीबी एवं जापान) बलदेव पुरुषार्थ के मार्गदर्शन में की गई. बातचीत के बाद ऋण के कारार पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के उप सचिव सौरभ सिंह और एडीबी की ओर से भारत उसकी स्थानीय निदेशिका मियो ओका ने हस्ताक्षर किए.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि एडीबी की इस सहायता से चेन्नई में विकसित की जाने वाली परियोजना के तहत 170 किलोमीटर से अधिक लंबी जल आपूर्ति और सीवर पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा. इसके

विदेशी मुद्रा भंडार में 9.9 अरब डॉलर उछाल

मुंबई, 21 अगस्त देश के विदेशी मुद्रा भंडार में एक सप्ताह में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 14 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.9 अरब डॉलर बढ़कर 716.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया. भंडार में यह वृद्धि देश की बाहरी वित्तीय स्थिति के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है.

विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती से आयात भुगतान, वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव और विदेशी मुद्रा बाजार में संभावित दबाव से निपटने की क्षमता बढ़ती है.

खनिज सुधारों से बढ़ेगा निवेश

खनन क्षेत्र में शुल्क व्यवस्था होगी अधिक स्पष्ट और एकरूप

नए निवेश से उत्पादन बढ़ने और आयात निर्भरता घटने की उम्मीद

नई दिल्ली, 21 अगस्त. केंद्र सरकार की ओर से खनिज क्षेत्र में किए गए सुधारों का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्वागत किया है. कंपनी ने 17 अगस्त को अधिसूचित खनिज और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 2026 को खनन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है.

एसएआईएल के मुताबिक नए प्रावधानों से खनन क्षेत्र में वित्तीय व्यवस्था अधिक स्पष्ट और अनुमानित होगी तथा उद्योग को लंबे समय के लिए नीतिगत स्थिरता मिल सकेगी. इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ने और खनिज क्षेत्र में नए निवेश को गति मिलने की उम्मीद है.

कंपनी ने कहा कि संशोधन के बाद खनिजों पर कराधान और विभिन्न शुल्कों से जुड़े प्रावधानों में अधिक स्पष्टता और एकरूपता आएगी. साथ ही पूर्व में लंबित पूर्वव्यापी शुल्कों से जुड़े मामलों के समाधान में भी मदद मिलेगी. इससे कंपनियों को अपनी परियोजनाओं की लागत और वित्तीय व्यवहार्यता का बेहतर आकलन करने में मदद मिलेगी. एसएआईएल के लिए यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी लौह अयस्क और कोयले की कई कैप्टिव खदानों का संचालन करती है.

बीएपी के बढ़ते प्रभाव के बीच भाजपा का बड़ा दांव

कौन हैं मन्नालाल रावत जिन्हें मिली एसटी मोर्चे की कमान?

उदयपुर. दक्षिणी राजस्थान की जनजातीय राजनीति में भाजपा ने बड़ा दांव चला है. उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में रावत को अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद राजस्थान की आदिवासी राजनीति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.

माना जा रहा है कि भाजपा का यह फैसला दक्षिणी राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे भारत आदिवासी पार्टी यानी (बाप) के प्रभाव के बीच काफी अहम है. रावत लंबे समय से जनजातीय मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं और अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है.

डॉ. मन्नालाल रावत राजनीति में आने से पहले सरकारी सेवा में थे. उन्होंने परिवहन विभाग में संयुक्त कमिश्नर के पद पर काम किया और बाद में वीआरएस लेकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा. वर्ष 2024 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और उदयपुर से सांसद चुने गए. इसके बाद से ही वे जनजातीय समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय नजर आए हैं.

रावत को अनुसूचित जनजाति मोर्चे की राष्ट्रीय कमान मिलने को उनके राजनीतिक सफर में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है.

> **लोकसभा जीतने के बाद प्रमुखता से उठाई आदिवासी क्षेत्रों की आवाज**
> रावत खुद जनजातीय समाज से जुड़े मुद्दों पर लगातार बात करते रहे हैं. लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों और वहां के लोगों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया है. इसी वजह से उनकी नई जिम्मेदारी को दक्षिणी राजस्थान में भाजपा की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी अब जनजातीय समाज के बीच संगठन को और मजबूत करने के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर जोर दे सकती है. मन्नालाल रावत की जनजातीय मुद्दों पर पकड़ का एक कारण उनका अकादमिक जुड़ाव भी है.

मालवीय से क्या नाराजगी थी?

नई दिल्ली. आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय से पार्टी के आला नेताओं को क्या कोई नाराजगी थी, जो उनको हटा दिया गया? उनको हटाने के साथ साथ पूरी सोशल मीडिया टीम को बदल दिया गया.

इतना ही नहीं मालवीय के समय जिसे आईटी सेल कहा जाने लगा था उसका नाम फिर से सोशल मीडिया टीम कर दिया गया है. कई जानकारों का कहना है कि मालवीय की वजह से आईटी सेल इतना बदनाम हो गया था कि उसका भी नाम बदला गया. हालांकि दूसरी ओर अब भी कई लोग मान रहे हैं कि मालवीय को हटाने का फैसला टैक्टिकल है, पार्टी के नेताओं को उनसे कोई नाराजगी नहीं है.गौरतलब है कि अमित मालवीय को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी. वे सह प्रभारी थे. आईटी सेल का काम देखने के साथ साथ वे बंगाल चुनाव में भी भूमिका निभा रहे थे. इसलिए एकदम उनको हाशिए पर नहीं डाला जाएगा. उनके लिए आगे कोई न कोई भूमिका तय होगी. उनकी क्या भूमिका होगी यह इस पर भी निर्भर करेगा कि नई टीम कैसा काम करती है. छत्तीसगढ़ में नितिन नबीन के साथ काम कर चुके दीपक म्हस्के को सोशल मीडिया प्रमुख बनाया गया है.

अकाली दल बिना भाजपा का नया नेतृत्व तैयार

जालंधर. भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सिख राजनीति को नया स्वरूप देना शुरू किया है. पार्टी अब शिरोमणि अकाली दल के साथ राजनीतिक गठजोड़ तक सीमित नहीं रहना चाहती. इसका लक्ष्य सिख समुदाय के भीतर अपने स्वतंत्र नेतृत्व का आधार मजबूत करना है. इसी रणनीति के तहत भाजपा ने कई प्रमुख सिख चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं. पंजाब की कुल आबादी में सिखों की हिस्सेदारी करीब 57.7 फीसदी है. राज्य की राजनीति में सिख समुदाय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. सिख समाज में जाट सिख समुदाय का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव विशेष रहा है. पंजाब की खेती-किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनकी मजबूत मौजूदगी है.

अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जाट सिख नेतृत्व प्रभावशाली रहा है. भाजपा अब इसी प्रभावशाली सामाजिक आधार में अपनी राजनीतिक जगह बनाने का प्रयास कर रही है. पार्टी अब केवल हिंदू शहरी मतदाताओं तक सीमित नहीं रहना चाहती है. वह ग्रामीण पंजाब और सिख समाज में अपनी स्वतंत्र स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है. राजनीतिक माहिर डीएवी के प्रोफेसर कुणाल के अनुसार, जाट सिख नेतृत्व को नजरअंदाज करना आसान नहीं. भाजपा को सिख समाज के विभिन्न वर्गों और ग्रामीण जाट सिख मतदाताओं के बीच जगह बनानी होगी.

भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य इकबाल सिंह लालपुरा सिख प्रतिनिधित्व का प्रमुख चेहरा हैं. हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी मिली हुई है.

> **पंजाब में नेतृत्व विस्तार**
> पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को भाजपा की राष्ट्रीय टीम में उपाध्यक्ष बनाया गया है. इससे पंजाब के सिख नेतृत्व को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में अधिक स्थान मिला है. पंजाब भाजपा की कमान केवल सिंह ढिल्लों को सौंपना भी इसी रणनीति का हिस्सा है. सिख चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने सिख मतदाताओं तक सीधा संदेश दिया है. यह पहली बार है जब पंजाब में कोई जाट सिख चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बना है. पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय जिम्मेदारी छोड़ी है.

विशेष | **शुभेंदु अधिकारी ने 100 दिनों में बदला बंगाल का माहौल**

ममता बैकफुट पर, लेफ्ट-कांग्रेस बेदम

कोलकाता. 4 मई 2026, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम ने पूर्वी भारत की राजनीतिक तस्वीर बदल गई. अंग-बंग और कलिंग में बीजेपी का शासन हो गया. जिस पश्चिम बंगाल में 34 साल लगातार वाम दलों और 15 साल तृणमूल कांग्रेस की सत्ता रही, वहां बीजेपी का भगवा परचम लहराने लगा. 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ली.

सीएम की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए. राज्य के राजनीति में उठापटक भी हुई. चुनाव नतीजों आने के बाद एक महीने के अंदर टीएमसी विधायक दल और संसदीय दल के टुकड़े हो गए. 100 दिनों में राजनीति ऐसी बदली कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का कुनबा बैकफुट पर है. टीएमसी न सिर्फ संसद और विधानसभा में बल्कि पंचायतों में भी कमजोर हो गई. कांग्रेस और वाम दल नजर नहीं आ रहे हैं.

शुभेंदु ने बड़े फैसले लिए- पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सामने सरकार बनाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ब्यूरोक्रेसी को काबू करने की थी. 15 साल में टीएमसी शासन के दौरान वेस्ट बंगाल पुलिस सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर काम करने के आरोप लगे थे. सीएम शुभेंदु ने अफसरों की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त कदम उठाए. अफसरों का पॉलिटिकल मंचों पर आना-जाना बंद कराया. पुलिस को प्रफेशनल तरीके से काम करने की नसीहत दी. टीएमसी राज में जमे विवादित अफसरों के तबादले किए. तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों और आरजी कर रेप केस जैसे मामलों की जांच शुरू कराई. सीबीआई समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों को दोबारा पश्चिम बंगाल में एंट्री के आदेश दिए. बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े जिलों में बीएसएफ को खुली छूट दी. वंदे मातरम, बांग्लादेश बॉर्डर, दीघा जगन्नाथ धाम जैसे मुद्दों पर बीजेपी के स्टैंड को लागू किया.

पुराने केस खोले, चुनावी वादे भी किए पूरे-बीजेपी सरकार ने जनता के बीच किए गए चुनावी वादों को पूरा करना शुरू किया. रियायती दर पर मछली चावल खिलाने के लिए कैंटीन खोली गई. 1 जून से महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की सहायता देने वाली अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी गई. मौलवियों की सरकारी सैलरी बंद की गई. धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सरकारी सहायता को भी खत्म कर दिया गया.

> **बंगाल के ट्रेंड से अलग गए शुभेंदु अधिकारी**
> राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि इस बदली राजनीति में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति के अनुभवों का इस्तेमाल किया. अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी शासन का दौर शुरू हुआ है. पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास में एक पार्टी का लंबे समय तक सत्ता में रहने का ट्रेंड रहा है. जब सत्ता बदलती है कि जिला स्तर से राजधानी कोलकाता तक पॉलिटिकल सिस्टम बदलता है. 2011 में सत्ता हासिल करने के बाद वाम दलों के ग्राउंड नेटवर्क पर कब्जा किया था. शुभेंदु अधिकारी इस ट्रेड से उलट चल रहे हैं. उन्होंने उस नेटवर्क पर ही धावा बोला है, जो सत्ता के साथ धीरे से चिपक जाते हैं. फिलहाल शुभेंदु अधिकारी ने 100 दिनों में विपक्ष की हालत कमजोर कर दी है. नगर निकाय और पंचायत चुनाव में यह पता चलेगा कि उनका दांव कितना सटीक साबित हुआ.